

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3011 का उत्तर

देश भर में नई/निर्माणाधीन/लंबित रेल परियोजनाएं

3011. श्री अरुण कुमार सागर:

श्री थरानिवेधन एम. एस.:

श्रीमती मंजू शर्मा:

श्री अजय भट्ट:

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रेल मंत्रालय को उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो अब तक स्वीकृत और लंबित प्रस्तावों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ख) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर राजस्थान में, नई/निर्माणाधीन/लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है/विलंब के क्या कारण हैं तथा ये परियोजनाएं राज्य-वार, ज़ोन-वार और परियोजना-वार कब से लंबित हैं;
- (घ) अपने निर्धारित समय-सारणी से पीछे चल रही परियोजनाओं की संख्या कितनी हैं और इन परियोजनाओं में विलंब के परियोजना-वार कारण क्या है तथा इनकी लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटित निधियों और अब तक किए गए व्यय का विशेषकर तमिलनाडु, जिसमें अरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है का ब्यौरा क्या है;
- (च) निधियों की कमी के कारण रुकी हुई/लंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

- (छ) क्या इन परियोजनाओं के व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ज) इन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है और रेल बुनियादी ढांचे में सुधार पर इनका क्या अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा; और
- (झ) इन परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने और विलंब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (झ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेलों के अनुसार किया जाता है न कि राज्य-वार/जिला-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य/जिला की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के लिए राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालयों इत्यादि सहित विभिन्न स्तरों पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्ताव/शिकायतें/सुझाव प्राप्त होना एक सतत और चलायमान प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में, 35,966 किलोमीटर लंबाई की 431 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (154 नई लाइन, 33 आमान परिवर्तन और 244

दोहरीकरण) लगभग 6.75 लाख करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत की गई हैं। इन कार्यों की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई एनएल/जीसी/डीएल (कि.मी. में)	कमीशन की लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	154	16,142	3,036	1,45,318
आमान परिवर्तन	33	4,180	2,997	22,753
दोहरीकरण/ बहुपथन	244	15,644	6,736	1,22,858
कुल	431	35,966	12,769	2,90,929

सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

भारतीय रेल में नए रेलपथ बिछाने/कमीशन करने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-25	34,428 कि.मी.	8.6 कि.मी. प्रति वर्ष (2 गुना से अधिक)

पिछले 3 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, भारतीय रेल में कुल 67,010 किलोमीटर लंबाई के 982 सर्वेक्षण (295 नई लाइन, 13 आमान परिवर्तन और 674 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

उत्तराखंड:

उत्तराखण्ड राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं एवं संरक्षा कार्यों हेतु बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	187 करोड़ रु. प्रति/वर्ष
2025-26	4,641 करोड़ रु. (लगभग 25 गुना)

01.04.2025 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली ₹40,384 करोड़ की लागत पर 216 कि.मी. कुल लंबाई को कवर करने वाली 03 नई रेल लाइनों को स्वीकृत किया गया है जिनमें से 16 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2025 तक ₹19,898 करोड़ का व्यय उपगत किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	03	216	16	19,898

चारधाम को रेल संपर्कता मुहैया कराने के लिए ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई लाइन परियोजना (125 कि.मी.) स्वीकृत की गई है।

इस परियोजना का संरेखण उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले से होकर गुजरता है और यह ऋषिकेश और भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ देवप्रयाग और कर्णप्रयाग के धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों से रेल संपर्कता प्रदान करेगा।

परियोजना का संरेखण मुख्यतः सुरंगों से होकर गुजरता है। इस परियोजना में 104 कि.मी. लंबाई की 16 मुख्य लाइन सुरंगों और लगभग 98 कि.मी. लंबाई की 12 एस्केप सुरंगों का निर्माण शामिल हैं। अब तक 99 कि.मी. लंबाई की मुख्य सुरंगें तथा 94 कि.मी. से अधिक लंबाई की 09 एस्केप सुरंगें पूरी की जा चुकी हैं।

निर्माण कार्यों की प्रगति में वृद्धि करने के लिए विभिन्न सुरंगों में 08 एडिट्स की पहचान की गई है। इन एडिट्स के माध्यम से सुरंग उत्खनन के अतिरिक्त कार्य सृजित हुए, जिससे लंबी सुरंगों को शीघ्र पूरा करने में तेजी आई है। सभी 08 एडिट्स (5 कि.मी.) के कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं।

इस परियोजना में 19 महत्वपूर्ण/बड़े पुलों का निर्माण भी शामिल है। 19 महत्वपूर्ण/बड़े पुलों में से 8 का निर्माण भी पूरा हो चुका है। शेष पुलों के निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं।

गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक रेल संपर्कता के विस्तार करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बहरहाल, परियोजना का संरेखण हिमालय के मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट के पास स्थित है जो अत्यधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय है।

राजस्थान

हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	682 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	9,960 करोड़ रु. (लगभग 15 गुना)

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	798 कि.मी.	159.60 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-25	3,815 कि.मी.	346.82 कि.मी. प्रति वर्ष (2 गुना से अधिक)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 43,918 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 3,409 कि.मी. लंबाई की 28 रेल परियोजनाएँ (13 नई लाइन, 05 आमामान परिवर्तन और 10 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है। इन कार्यों की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	13	981	196	5769
आमामान परिवर्तन	5	1252	788	6829
दोहरीकरण/ बहुपथन	10	1176	254	6357
कुल	28	3,409	1,238	18,954

सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत (करोड़ रु. में)
1.	बंगुरग्राम-रास नई लाइन (28 किलोमीटर)	175
2.	थईयात हमीरा-सोन् नई लाइन (58 किलोमीटर)	350
3.	सूरतपूड़ा-श्रीगंगानगर आमान परिवर्तन (241 किलोमीटर)	896
4.	सादुलपुर-बीकानेर एवं रतनगढ़-डेगाना आमान परिवर्तन (438 किलोमीटर)	886
5.	जयपुर-चुरू एवं सीकर-लोहारू आमान परिवर्तन (320 किलोमीटर)	1105
6.	भगत की कोठी-लूनी दोहरीकरण (28 किलोमीटर)	128
7.	रानी-केशव गंज दोहरीकरण (59 किलोमीटर)	290
8.	गुड़िया-मारवाड़ एवं करजोदा-पालनपुर दोहरीकरण (49 किलोमीटर)	251
9.	रानी-मारवाड़ दोहरीकरण (52 किलोमीटर)	346
10.	आबू रोड-स्वरूप गंज दोहरीकरण (26 किलोमीटर)	195
11.	आबू रोड-सरोत्रा रोड दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	152
12.	अलवर-बाँदीकुई दोहरीकरण (60 किलोमीटर)	450
13.	अजमेर-बंगुरग्राम दोहरीकरण (48 किलोमीटर)	375
14.	बंगुरग्राम-गुड़िया कहीं-कहीं दोहरीकरण (47 किलोमीटर)	395
15.	डेगाना-राई का बाग दोहरीकरण (146 किलोमीटर)	809
16.	बीना-कोटा दोहरीकरण (282 किलोमीटर)	2476
17.	नीमच-चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण (56 किलोमीटर)	560
18.	दौसा-गंगापुर सिटी दोहरीकरण (93 किलोमीटर)	950
19.	फुलेरा-डेगाना दोहरीकरण (108 किलोमीटर)	702
20.	चुरू-रतनगढ़ दोहरीकरण (43 किलोमीटर)	423
21.	खाटूवास-नारनौल दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	313

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली कुछ मुख्य परियोजनाओं जो हाल ही में शुरू की गई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1.	नीमच-बड़ी सादड़ी नई लाइन (48 किलोमीटर)	495
2.	तरंगा हिल-आबू रोड नई लाइन (116 किलोमीटर)	2798
3.	रामगंजमंडी-भोपाल नई लाइन (277 किलोमीटर)	5073
4.	पुष्कर-मेड़ता नई लाइन (51 किलोमीटर)	800
5.	रींगस-खाटू श्याम जी नई लाइन (17 किलोमीटर)	254
6.	मेड़ता सिटी-रास नई लाइन एवं मेड़ता रोड स्टेशन पर बाई पास (56 किलोमीटर)	947
7.	कोटा विस्तार सहित ग्वालियर-शयोपुर कलां आमामान परिवर्तन (284 किलोमीटर)	2913
8.	गंगापुर सिटी के लिए विस्तार सहित धौलपुर-सिरमथरा आमामान परिवर्तन (145 किलोमीटर)	747
9.	मावली-देवगढ़ मदारिया आमामान परिवर्तन (83 किलोमीटर)	969
10.	मथुरा-झांसी तीसरी लाइन (274 किलोमीटर)	5924
11.	आगरा फोर्ट-बांदीकुई दोहरीकरण (150 किलोमीटर)	988
12.	सवाई माधोपुर-जयपुर दोहरीकरण (131 किलोमीटर)	1204
13.	चूरू-सादुलपुर एवं लूनी-भिलड़ी दोहरीकरण (330 किलोमीटर)	3554
14.	अजमेर-चंदेरिया दोहरीकरण (178 किलोमीटर)	1635
15.	सवाईमाधोपुर में बाई पास लाइन (14 किलोमीटर)	304
16.	रेवाड़ी-खाटूवास दोहरीकरण (28 किलोमीटर)	352
17.	मारवाड़ में बाई पास लाइन (4 किलोमीटर)	71
18.	चुरू में बाईपास लाइन (5 किलोमीटर)	63
19.	समदड़ी में बाईपास लाइन (1 किलोमीटर)	26
20.	रामदेवरा-पोखरण नई लाइन (13 किलोमीटर)	189
21.	लालगढ़-बीकानेर पूर्व केबिन का दोहरीकरण (11 किलोमीटर)	279
22.	रींगस-सीकर दोहरीकरण (50 किमी)	470

विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 5,666 कि.मी लंबाई की कुल 59 परियोजनाओं (25 नई लाइन और 34 दोहरीकरण) का सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।

तमिलनाडु

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में काफी वृद्धि हुई है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	879 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	6,626 करोड़ रुपए (7.5 गुना से अधिक)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 22,808 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1,700 किलोमीटर लंबाई की 15 परियोजनाएं (9 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 03 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं। इनका सारांश निम्नलिखित है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	9	812	24	1,337
आमान परिवर्तन	3	748	604	3471
दोहरीकरण/बहुपथन	3	140	37	2783
कुल	15	1,700	665	7,591

सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/वर्षवार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन्हें हाल ही में पूरा किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	दिंडुक्कल-पलानी-पोलाची आमान परिवर्तन (121 किलोमीटर)	610
2	पोलाची-पालघाट आमान परिवर्तन (56 किलोमीटर)	350
3	पोलाची-पोत्तनूर आमान परिवर्तन (40 किलोमीटर)	400
4	क्विलोन-तिरुनेलवेली-तिरुचेंदुर आमान परिवर्तन (357 किलोमीटर)	1122
5	मयिलादुतुरई-थिरुवरुर-कराइक्कुडी आमान परिवर्तन (187 किलोमीटर)	1338
6	मदुरै-बोडियाकन्नूर आमान परिवर्तन (90 किलोमीटर)	593
7	चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	670
8	तिरुवल्लुर-अराक्कोनम चौथी लाइन (27 किलोमीटर)	83
9	चेन्नै सेंट्रल-बेसिन ब्रिज दोहरीकरण (2 किलोमीटर)	31
10	तंजावूर-पोनमलाई दोहरीकरण (48 किलोमीटर)	370
11	विल्लुपुरम-दिंडुक्कल दोहरीकरण (273 किलोमीटर)	2000
12	चेन्नै बीच-कोरुकुपेट तीसरी लाइन (5 किलोमीटर)	168
13	चेन्नै बीच-अट्टीपट्टू चौथी लाइन (22 किलोमीटर)	293
14	ओमलुर-मेत्तूरडैम कहीं-कहीं दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	327
15	चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम और तांबरम-चेंगलपट्टू - तीसरी लाइन (133 किलोमीटर)	1122
16	सेलम-मैग्नेसाइट जंक्शन-ओमालुर दोहरीकरण (11 किलोमीटर)	115
17	मदुरै - मनियाची-तूतीकोरिन दोहरीकरण (160 किलोमीटर)	1891
18	मनियाची-नागरकोइल दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	1752
19	चेन्नै बीच- चेन्नै एगमोर दोहरीकरण (4 किलोमीटर)	272
20	कारैक्काल -पेरलम नई लाइन (23 किलोमीटर)	373
21	कारैक्काल पोर्ट से उत्तरी छोर बंदरगाह तक सम्पर्कता (1 किलोमीटर)	18

अरणी में संपर्कता बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	टिंडीवनम-नगरी नई लाइन (184 किलोमीटर)	3,631
2	टिंडीवनम-तिरुवण्णामलै नई लाइन (71 किलोमीटर)	1400

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली कुछ परियोजनाएँ, जिन्हें शुरू किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	मोरप्पुर-धर्मपुरी नई लाइन (36 किलोमीटर)	359
2	नागपट्टिनम - तिरुतुरईपुंडी नई लाइन (43 किलोमीटर)	742
3	तिरुवनंतपुरम - कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 किलोमीटर)	3785
4	अराक्कोनम यार्ड तीसरी और चौथी लाइन (6 किलोमीटर)	98
5	इरुगुर-पोत्तनूर दोहरीकरण (11 किमी)	277
6	तांबरम-चेंगलपट्टू चौथी लाइन (30 किमी)	757
7	अत्तिपट्टू-गुम्मीडिपुंडी तीसरी और चौथी लाइन (23 किमी)	365
8	पेरम्बूर-अंबत्तूर 5वीं और 6वीं लाइन (6 किमी)	182
9	तिरुपति-पाकाला-काटपाडी दोहरीकरण (104 किमी)	1332
10	अत्तिपट्टू-पुत्तूर नई लाइन (88 किमी)	1700
11	महाबलीपुरम नई लाइन (179 किमी) के रास्ते चेन्नै - कडलूर	2670

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली कुल 2,478 कि.मी. लंबाई वाले 29 सर्वेक्षण (06 नई लाइन और 23 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए कुल अपेक्षित भूमि	4,326 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	1052 हेक्टेयर (24%)
अधिग्रहण हेतु शेष भूमि	3274 हेक्टेयर (76%)

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हुई कुछ मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	तिंडीवनम-तिरुवण्णामलै नई लाइन (71 किलोमीटर)	276	33	243
2.	अत्तिपट्ट-पुत्तुर नई लाइन (88 किलोमीटर)	189	0	189
3.	मोरप्पुर-धर्मपुरी नई लाइन (36 किलोमीटर)	92	45	47
4.	मन्नारगुडी-पट्टुकोट्टई नई लाइन (41 किलोमीटर)	196	0	196
5.	तंजावूर-पट्टुकोट्टई नई लाइन (52 किलोमीटर)	152	0	152

इसके अलावा, रामेश्वरम-धनुषकोडि नई लाइन (18 कि.मी.) को 734 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना का शिलान्यास 01.03.2019 को किया गया था। बहरहाल, परियोजना शुरू नहीं की जा सकी है क्योंकि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू नहीं किया गया है।

भारत सरकार इस परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तैयार है, तथापि इनकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात अनुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आरंभिक और अंतिम छोर संपर्कता
- मिसिंग लिंकों का संयोजन और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्द्धन
- राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्नानुसार हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंजूरी
- बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां
- क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि।

- फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी।
- शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान।
